Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
January-June 2022 3(1), 1224–1228

INDIA AND THE CARTAGENA CONFERENCE

भारत और कार्टेग्ना सम्मेलन

Vinod Kumar [1]

[1] SF, Post Doctorate, Ph.D., M.Phil., UGC Net & Lecturer, Department of Political Science, Government College Bahadurgarh, India

Corresponding Author

Vinod Kumar, vinodkchahar@gmail.com

DOI

10.29121/shodhkosh.v3.i1.2022.6363

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2022 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

ABSTRACT

English: The present research paper evaluates the Cartagena (1995) Conference of the Non-Aligned Movement. Through the conference, an attempt is also made to clarify what kind of role India played in this conference. New programs were approved in the final declaration of this conference. 64 point proposals were accepted in a special meeting of member countries. And along with this, this conference was also important because the member countries outlined their economic priorities for the first time. The leaders were of the view that after getting rid of the political tensions before the Cold War, dialogue should be promoted among the developing countries to fulfill the commitment of the Non-Aligned Movement to eradicate illiteracy and poverty. This research paper is also published in International Journal of Advanced Research and Development, July 2016.

Hindi: वर्तमान शोध पत्र गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के कार्टेग्ना (1995) सम्मेलन का मूल्यांकन करता है सम्मेलन के माध्यम से यह भी स्पष्ट करने का प्रयास है कि भारत ने इस सम्मेलन में किस प्रकार की भूमिका निभाई। इस सम्मेलन के अंतिम घोषणा पत्र में नए कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई। सदस्य देशों की विशेष बैठक में 64 सूत्रीय प्रस्ताव स्वीकृत किये गए। तथा इसके साथ ही यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा कि सदस्य देशों ने पहली बार अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। नेताओं का विचार था कि शीतयुद्ध से पहले के राजनैतिक तनावों से छुटकारा पाने के बाद निरक्षरता और गरीबी उन्मूलन की गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए विकासशील देशों के बीच बातचीत को बढावा दिया जाना चाहिए। यह शोध पत्र इ्रटरनेशनल जनरल आॅफ एडवांस रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट, जुलाई 2016 में भी प्रकाशित है।

Keywords: Democratization, Developing Countries, Disarmament, Non-Aligned Movement, Post-Cold War Era लोकतान्त्रिकरण, विकासशील देश, निरस्त्रीकरण, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन, शीतयुद्धोत्तर युग

1. प्रस्तावना

प्रस्तुत विश्लेषण कार्टेग्ना सम्मेलन के मूल्यांकन एवं भारत की भूमिका से संबंन्धित है इसमें द्वितीयक स्त्रोतों का सहारा लिया गया है। लोकतन्त्र, विकास तथा वैश्विक समानता आदि चरों का प्रयोग किया गया है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन कार्टेग्ना सम्मेलन इस वैश्विक संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि शीतयुद्ध की समाप्ति के उपरान्त वैश्विक स्तर पर अनेक परिवर्तन हुए थे। और इन्हीं बदलावों के संदर्भ मंे सदस्य राष्ट्रों ने इस आन्दोलन के मंच से इसकी आन्तरिक कार्यप्रणाली, आर्थिक विकास के लिए पहल तथा वैश्विकरण के उदय के बाद गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की प्रसंगिकता को बनाए रखने के लिए अपने महत्वपूर्ण सूझाव प्रकट किए। इन सूझावों में सबसे प्रमुख था संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के सिद्धान्तों और उद्देश्यों पर आधारित एक न्यायसंगत और समतामूलक विश्व व्यवस्था की स्थापना की जाए। सदस्य राष्ट्रों का मानना था कि शीतयुद्ध की समाप्ति से अपेक्षित शान्ति तथा विकास के अवसरों की शुरूआत नहीं हुई जिसकी अपेक्षा विकासशील देशों को थी। इसलिए वैश्विक समुदाय को सामूहिक रूप से शान्ति, न्याय, राष्ट्रों के मध्य समता, लोकतंत्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित विश्व व्यवस्था की दिशा में प्रयास करना होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी राष्ट्रों ने चिन्ता जताई कि विकसित देशों में अपनी सुरक्षा को लेकर जो सहयोग तथा पहल की जा रही है इसका नकारात्मक प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए सभी सदस्य राष्ट्रों ने इस बात पर बल दिया कि विकसित देश लम्बे समय से चले आ रहे विवादांे का शिघ्र समाधान करें तथा

पुराने मतभेदों को फिर से उभरने से रोकें और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सामूहिक सरुक्षा के सिद्धान्तों को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में काम करें।

कार्टेग्ना सम्मेलन: गुटनिरपेक्ष देशों का ग्यारहवां शिखर सम्मेलन 18 से 20 अक्टूबर, 1995 को कार्टेग्ना में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 113 देशों ने भाग लिया। कोलम्बिया के राष्ट्रपति इरनेस्टो सैम्पर पिजानों ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जरनल सुहार्तो से 113 सदस्यीय निर्गुट आन्दोलन की अध्यक्षता ग्रहण की। इस सम्मेलन की यह महत्वपूर्ण विशेषता थी कि किसी दक्षिण अमेरिकी देश में यह दूसरा सम्मेलन था।1 मतभेद वाले सभी द्विपक्षीय मुद्दों को दरकिनार करते हुए सम्मेलन का आरम्भ इस आशा के साथ हुआ कि सम्मेलन गरीब और विकासशील देशों की बेहतरी के लिए विकासोन्मुख अधिपत्र तैयार करेगा। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन में वैश्विक, राजनैतिक, क्षेत्रीय, आर्थिक, सामाजिक, आन्दोलन की प्रासंगिकता, नई अन्तर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था, एन.पी.टी. आदि विषयों पर भी व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया।2 आन्दोलन के नए अध्यक्ष ने कहा कि अब आन्दोलन को टकराव की अपेक्षा सहयोग और विश्व शान्ति स्थापित करने वाले कार्यक्रम निर्धारित करने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिकता का अर्थ आन्दोलन को प्रेरित करने वाले सिद्धान्तों को छोड़ना नहीं है बल्कि उनमें समन्वय स्थापित करना है।3

गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने इस सम्मेलन में पुनः जोरदार ढंग से संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतान्त्रीकरण की बात उठाई। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि संयुक्त राष्ट्र की निर्णय -निर्माण प्रक्रिया में महासभा एक उच्च एवं विचारशील अंग है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान ढांचे में सुधार आवश्यक है फिर भी इस संदर्भ में उन्होंने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसमूह का प्रस्ताव रखा जो कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। इस बात पर बल दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावशीलता और क्षमता को बढ़ाने के लिए इसकी पुनः संरचना अति आवश्यक है। परन्तु इस प्रकार के कार्य समूहों को संयुक्त राष्ट्र संघ की विकासात्मक गतिविधियों को कमजोर नहीं करना चाहिए। सम्मेलन के अन्तिम घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया कि गुटनिरपेक्ष देशों को महासभा तथा सुरक्षा परिषद के साथ संबंधों को अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।4 सदस्य राष्ट्रों ने विकसित राष्ट्रों से आग्रह किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरणों का लोकतान्त्रीकरण सभी राष्ट्रों की प्रभुसत्ता तथा समानता के आधार पर होना चाहिए ताकि यह संपूर्ण रूप से एक वैश्विक प्रकृति का संगठन प्रतीत हो। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा- 50 के क्रियान्वयन पर ध्यान देने के साथ-साथ इस बात का भी स्वागत किया कि इसके कार्यों में निश्चित रूप से पारदर्शिता है। परन्तु समय की मांग है कि इसे और अधिक पारदर्शी बनाया जाए और धारा 109 के अनुसार इसकी पुनर्संरचना की जाए।5

क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका से दो-दो सदस्यों को सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एशिया में सर्वाधिक आबादी वाला चीन पहले से ही स्थाई सदस्य है, अतः भारत की बेहतर संभावनाएं हैं।6 भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि ''गुटनिरपेक्ष आन्दोलन सच्चाई एवं न्याय के लिए पेरवी करने वाला सशक्त संगठन है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ को भी सच्चाई और न्याय के लिए कार्य करना चाहिए। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपने सम्बन्धों को बिना किसी भय एवं पक्षपात के क्रियान्वित करना चाहिए।... मैं यहां कहना चाहूंगा कि हमें अपने मतभेदों को भुलाकर, सुरक्षा परिषद को भोगोलिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से अधिक लोकतान्त्रिक बनाने सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। हमारा विचार है इस प्रकार की पहल से विकासशील देशों की भावनाओं और प्राथमिकताओं को मान्यता मिलेगी।''7 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार संबंधी भारतीय प्रस्ताव को अन्तिम घोषणा पत्र में स्थान मिल गया जबकि पाकिस्तान ने इसका यह कहते हुए विरोध किया था कि यह कुछ देशों को विशेषाधिकार देने वाली बात है। घोषणा पत्र में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार कर इसमें लैटिन अमेरिका, एशिया, कैरेबियाई क्षेत्र और अफ्रीका से ज्यादा संख्या में सदस्य रखे जाएं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि सुरक्षा परिषद का विस्तार करते समय यदि गुटनिरपेक्ष देशों की उपेक्षा की गई तो आन्दोलन उसे बर्दास्त नहीं करेगा। भारत सहित सभी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का विचार था कि सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि इसके विस्तार का प्रस्ताव व्यापक हो ताकि यह संगठन वास्तविक एवं विश्व संगठन की शर्तों को पूर्ण कर सके।8

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देशों ने हमेशा की तरह इस सम्मेलन में अपनी सभी समस्याओं के लिए विकसित राष्ट्रों पर आरोप लगाने की अपेक्षा अपने सदस्यों के लिए कार्य निर्धारित किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अपने सैन्य बजट में कटौती करने की वचनबद्धता है। सम्मेलन में उपस्थित सभी सदस्यों ने कोलंबिया आह्वान दस्तावेज अंगीकृत करते हुए कहा कि हम शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष अपनी जनता के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करने के लिए सैन्य व्यय में कटौती करेंगे तथा हम निरस्त्रीकरण के उद्देश्य और परमाणु हथियारों के उन्मूलन समेत सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण को हासिल करने के लिए अपने प्रयासों को और गति प्रदान करेंगे।9 नाभिकीय परीक्षण और निरस्त्रीकरण पर विचार व्यक्त करते हुए कहा गया कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के माध्यम से सदस्य राष्ट्रों ने हमेशा निरस्त्रीकरण का स्वागत किया है परन्तु हम एन.पी.टी. का विरोध करते हैं। सदस्य राष्ट्रों ने आरोप लगाया कि एन.पी टी. की धारा टप् को परमाणु सम्पन्न राष्ट्र नजरअदांज कर रहे हैं तथा गैर नाभिकीय राष्ट्रों को इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर रहे हैं।10 राव ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत नाभिकीय हथियारों के पूर्ण सफाये के लिए प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शीघ्र वार्ता का इच्छुक है। राव ने आगे कहा कि ''शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सामरिक सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन आया है। इससे पहले परमाणु सम्पन्न राष्ट्र इन हथियारों को अपने अधिकार क्षेत्र में बनाए रखने पर अड़े हुए थे। यह सत्य है कि द्विपक्षीय समझोतों के माध्यम से ये राष्ट्र विश्व को 20,000 बार समाप्त करने की क्षमता से केवल 3000 बार समाप्त करने की क्षमता को कम करने पर सहमत हुए हैं। निश्चित रूप से ये राष्ट्र निरस्त्रीकरण के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध नहीं हंै जैसा कि वे इस संदर्भ में प्रचार करते रहे हैं। फिर भी हमें संयुक्त राष्ट्र हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण अभिकरण द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर कुछ संतोष है। इसमें दर्शाया गया है कि बहुत से देशों के रक्षा बजट में निश्चित

रूप से कमी आई है। 1987 में विभिन्न देशों का रक्षा बजट 1,260 अमेरिकी बिलियन डालर था जो 1993 में 868 अमेरिकी बिलियन डालर रिकार्ड किया गया। 1988 में 37 एशियाई देशों में भारत का रक्षा खर्च 5.24 था जो 1994 में घटकर 3.14 प्रतिशत रह गया।''11

राव ने भारत द्वारा 1988 में प्रतिपादित कार्य योजना, जिसमें संपूर्ण विश्व को परमाणु हथियार मुक्त एवं अहिंसा पर आधारित विश्व की कल्पना की थी, को पुनः दोहराया। उन्होंने कहा कि आज हमें शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व और अहिंसा पर आधारित विश्व व्यवस्था की आवश्यकता है। इसलिए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को इस प्रकार की कार्य योजना स्वीकार करनी चाहिए तथा सकारात्मक कदम उठाने चाहिए।12 उन्होंने सी.टी.बी.टी. पर शीर्घ वार्ता का अनुमोदन किया और नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर सार्वभौमिक रूप से नए मानदण्ड निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं होता है तो कुछ राष्ट्रों द्वारा संगणक के माध्यम से अति सूक्ष्म एवं भयावह हथियारों के परीक्षण किए जायेंगें जिसके परिणामस्वरूप मानवता के विनाश का खतरा बढेगा। जब कमी भी इन हथियारों का प्रयोग हुआ तो उन परिस्थितियों में संगणक आधारित तकनीक विहिन राष्ट्र मूक दर्शक बने रहेंगें।13 उन्होंने छोटे और हल्के हथियारों के विस्तार पर रोक लगाने की आवश्यकता जताई और यह भी कहा कि इस प्रकार के हथियार आतंकवादी गतिविधियों में इजाफे का मूल कारण है। इस तरह के जानलेवा हथियारों से, जैसे कि भूमिगत विस्फोटक आर.डी.एक्स इत्यादि से सिर्फ भारत में एक विस्फोट से लगभग दर्जनों जाने जाती हैं।14 अतः इस और भी सदस्य राष्ट्रों को गंभीरता से विचार करना होगा।

सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों ने पहली बार अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को रेखाँकित किया। इन नेताओं ने कहा कि शीत युद्ध से पहले के राजनैतिक तनावों से निजात पाने के बाद, निरक्षरता और गरीबी उन्मूलन की गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए, विकासशील देशों के मध्य बातचीत को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अन्तिम दस्तावेज में कहा गया कि हम संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेनवुड्स संस्थाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय वितीय प्रणाली के पुनर्गठन, उसके पुनजीर्वन और लोकतान्त्रिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना जारी रखेंगे और यह सब राष्ट्रों की प्रभुत्व सम्पन्न समानता के सिद्धान्त पर आधारित होगा। दस्तावेज में कहा गया कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सभी देश अपने उपर जबरदस्ती लादी जाने वाली शर्तों, बल प्रयोग और एकपक्षीय कार्यवाहियों के साथ-साथ अपनी धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताओं पर विदेशी प्रभाव थोपने का सामूहिक विरोध करेंगे।15 इसमें कहा गया कि हम उपनिवेशवाद और उसके अवशेष के उन्मूलन के इच्छुक हैं और नई हस्तक्षेपवादी प्रवृतियों का विरोध करते हैं। इसमें विकासशील देशों के ऋण और विशेषकर बहुराष्ट्रीय कर्ज की समस्या को निपटाने पर भी बल दिया। सदस्य राष्ट्रों ने मांग की कि कम विकसित राष्ट्रों के कर्ज को माफ किया जाए।16 कोलंबिया घोषणा पत्र में आन्दोलन के अध्यक्ष पिजानों को औद्योगिक देशों के बीच वार्ता करने को अधिकृत किया गया क्योंकि उत्तर दक्षिण के बीच विकास, तकनीकी, ओद्योगिकी एवं विज्ञान को लेकर काफी असमानता है। विकासशील देशों में भुखमरी, गरीबी, निरक्षरता, पानी की समस्या आदि राष्ट्रीय समस्याएं हैं जिनको हल करने के लिए काफी मात्रा में धनराशि खर्च करनी पड़ती है। इससे ये राष्ट्र विकास की प्रक्रिया में पिछड़ते जा रहे हैं। अतः उत्तर-दक्षिण के राष्ट्रों के बीच आर्थिक संतुलन स्थापित किये जाने हैतु नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लागू होनी चाहिए।17

भारतीय प्रधानमंत्री ने आर्थिक विषयों पर अपने विचार रखते हुए कहा कि विकासशील देशों को स्वतंत्र रूप से अपनी सीमाओं से बाहर पूंजी निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह सत्य है कि विकासशील देश वेश्विक धारा में उदारीकरण की नीति अपना रहे हैं। इस प्रक्रिया में नवसंरक्षणवादी अनेक बहाने बनाकर इन देशों पर तरह-तरह की शर्तें और बंधन लगा रहे हैं। ये शर्तें मुख्यतः धनी राष्ट्रों द्वारा लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से थोपी जा रही है तथा पर्यावरण तथा बालश्रम इत्यादि के नाम पर इन्हें लगा रहे हैं।18 राव ने कहा कि वैश्वीकरण के कारण विकसित राष्ट्रों ने अपनी नीतियों में नई चुनौतियों और वास्तविकताओं को स्वीकार किया हैं परन्तु गुटनिरपेक्ष राष्ट्र बदलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश के अनुरूप अपनी नीतियों में आवश्यक परिवर्तन नहीं कर रहे है। ये राष्ट्र तकनीकि विकास पर बल नहीं दे रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इस प्रक्रिया में पिछड़ते जा रहे हंै। उन्होंने विश्वास जताया कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन विश्व के सभी गरीब देशों की सहायता के लिए तत्पर हैं और इस रूपान्तरण से उसमें कोई अस्थिरता नहीं आएगी। राव ने स्पष्ट किया कि हमें असहाय स्थिति की मानसिकता को बदलना होगा। दीर्घकालीन सामाजिक और आर्थिक विकास को केवल तभी दिशा मिलेगी जब उस राष्ट्र के लोगों को विकासात्मक कार्यों के लिए आत्मिक रूप से प्रेरित किया जाए।19

सम्मेलन में राष्ट्र प्रमुखों ने आतंकवाद पर गहरी चिन्ता जताते हुए कहा कि आतंकवादी गतिविधियों से प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्रों की एकता, मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन तथा संवैधानिक व्यवस्था प्रभावित हुई है। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करने की घोषणा पर संतोष जताते हुए इसका स्वागत किया और इसे शीर्घ लागू करने की वकालत की। उन्होंने सभी प्रकार के आतंकवाद से जुड़े प्रत्येक पहलू की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक देश के सामाजिक और आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा राष्ट्रों की एकता और अखण्डता को भी प्रभावित करता हैं, विशेषकर बहुलवादी समाजों को। इसलिए सदस्य राष्ट्रों ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मुहीम छेड़ने का अनुमोदन किया। अतः सभी सदस्य राष्ट्रों ने इस बात का समर्थन किया कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई लड़ी जाए और जहां कहीं भी आतंकवाद, चाहै वह क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसे मानवता के लिए खतरा माना जाएगा। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता में आतंक फैलाने वाली घटनाओं में संलग्न व्यक्तियों के समूह या व्यक्ति विशेष जो किसी भी उद्देश्य के लिए ऐसा कर रहे हैं उनको किसी भी आधार पर क्षमा नहीं किया जाएगा।20

सभी सदस्य राष्ट्रों ने यह संकल्प लिया की जो राष्ट्र आतंकवादियों की सहायता कर रहा है, उनमें भाग ले रहा है तथा एक देश के विरूद्ध आतंकवादी गतिविधियों को सक्रिय रूप से संचालित करने में अपने भू-भाग का प्रयोग करने की आज्ञा देता है तथा आतंकवादियों को प्रशिक्षण देता है, निश्चित रूप से उसके विरूद्ध; संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के उद्देश्यों, सिद्धान्तों एवं अन्य प्रावधानों, आचार सहिंताओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ठोस एवं कड़ी कार्यवाही की जाए। कोई भी राष्ट्र आतंकवाद को किसी भी प्रकार जैसे राजनीतिक, नैतिक, कूटनीतिक तथा भौतिक सहायता नहीं प्रदान करेगा।21

आन्दोलन के सदस्य देशों ने कोलंबिया आह्वान के अतिरिक्त एक और दस्तावेज स्वीकृत किया जिसमें कहा गया कि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों तथा मतभेदों का निपटारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्य शान्तिपूर्ण साधनों के द्वारा होना चाहिए।

सम्मेलन में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टों ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कश्मीर का मामला उठाकर, कश्मीर मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने का असफल प्रयास किया। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि ''कश्मीर विवाद की छाया एशिया महाद्वीप की शान्ति और स्थिरता पर पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की सूची में यह सबसे पुराना अनसुलझा मुद्दा है जिसने सबसे पहले इस समस्या के समाधान के लिए 1948 में आत्म-निर्णय के लिए जनमत संग्रह की बात कही थी। कश्मीर के लोगों ने मुसीबतों की लम्बी रातें गुजारी हैं और लगभग 40 हजार लोग मारे जा चुके हैं। महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है और बच्चों के अपहरण का मामला आम रहा है।''22 शिखर बैठक के आरम्भिक सत्र को सम्बोधित करते हुए राव ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने अवेध कब्जा कर रखा है उसे खाली कर दें। राव ने कहा इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के मध्य और कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हुआ है और यह एक प्रमाणिक तथ्य है कि जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य हिस्सा है।23 राव ने खेद व्यक्त किया कि नैम के मंच से द्विपक्षीय मामले नहीं उठाने की परम्परा को तोड़ते हुए भुट्टो ने आपसी मामलों को यहां उठाया। यह बात और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि तथ्यों को विकृत करके प्रस्तुत किया गया है। राव ने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ाओं का मूल कारण यह है कि राज्य में सक्रिय आतंकवादियों को बाहर से समर्थन मिल रहा है और यह निर्धारित करना मेरी सरकार का संकल्प है कि इन गतिविधियों से कश्मीर के निर्दोष नागरिकों पर कोई संकट न आए।24

जब राव भुट्टो की बात का जवाब दे रहे थे तो वह सभागार से अनुपस्थित थी। राव का भाषण शुरू होने के समय तो वह सम्मेलन कक्ष में थी लेकिन कुछ ही क्षण उपरान्त वह वहां से उठ गई। राव ने बात वहां से शुरू की जहां भुट्टो ने कश्मीर की तुलना बोस्निया हर्जेगोविना से की थी। बाद में राव की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर भुट्टो ने कहा कि वह उस समय सम्मेलन में उपस्थित नहीं थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री आसफ अहमद अली ने राव की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर मामले पर बातचीत करने को तैयार है परन्तु भारत कश्मीर के अलावा अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श चाहता है जो हमें स्वीकार नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने मंत्रिस्तरीय बैठक में पहले ही इस मुद्दे को उठाया था जिसके कारण शिखर बैठक की अन्तिम घोषणा के प्रारूप को अन्तिम रूप देने का काम रूक गया था। अतः स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने इस सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों के द्विपक्षीय विवादों के समाधान के लिए आन्दोलन द्वारा एक कार्यप्रणाली तय किए जाने की मांग की। परन्तु भारत ने पाकिस्तानी सुझाव का यह कहते हुए विरोध किया कि यह द्विपक्षीय विवादों में न पड़ने की इस आन्दोलन की परम्परा के विरूद्ध है।25 पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाकर उसे आत्म-निर्णय का मुद्दा बनाने का प्रयास किया लेकिन घोषण पत्र में इसे उपनिवेशवाद को समाप्त करने के संदर्भ में रखा गया। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्म-निर्णय का अधिकार किसी देश की राष्ट्रीय एकता और भौगोलिक अखंडता के विरूद्ध नहीं होना चाहिए। इस दस्तावेज में दुनियां के कुछ भागों में वहां के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की न्यायोचित मांग को बेरहमी से कुचले जाने की निन्दा की गई।26

राव ने कश्मीर का उल्लेख किए बिना कहा कि आतंकवाद को हर जगह से पूर्णरूप से समाप्त किया जाना चाहिए और छोटे और हल्के स्तर के हथियारों के उत्पादन और वितरण प्रणाली में उत्तरदायित्व एवं पारदर्षिता होनी चाहिए जो कि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अहम भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ''हमें अपनी नीतियों को समन्वित करने की आवश्यकता है जिससे सीमाओं की सुरक्षा, हथियार नियंत्रण, गैर कानूनी कार्यों और व्यापार के सम्बन्ध में प्रभावशाली मानदण्ड निर्धारित किए जा सकें।''27

राव ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता के संदर्भ में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद भी गुटनिरपेक्ष आन्दोलन प्रासंगिक है। शीत युद्ध के दौरान यह कहा जाता रहा है कि 'नैम' का उद्देश्य केवल दो शक्तिशाली सैनिक गुटों की शक्ति राजनीति से बचना है। परन्तु शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी यह आन्दोलन स्थाई शान्ति, वर्चस्व के विरूद्ध संघर्ष तथा नई विश्व-व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपना योगदान दे रहा है।28 हालांकि उन्होंने नई विश्व व्यवस्था की प्रकृति के बारे में कहा कि वर्तमान समय में गुटनिरपेक्षता कई विरोधी शक्तियों के मध्य बड़ी कार्यवाही है और यह इन बदलती हुई परिस्थितियों में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। आज ऐसा कोई पुराना विषय नहीं है जिससे गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका को कम आंका जाए।29

राव ने स्वीकार किया कि बदलते हुए परिवेश में आन्दोलन के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों को पुनः परिभाषित करने की आवश्कता है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन नई समस्याओं का सामना कर रहा है क्योंकि शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद पुरानी शक्तियों के गुटों का विघटन हो चुका है। कई सदस्य राष्ट्र इसके भविष्य को लेकर आशावान हैं तो दूसरी तरफ कई राष्ट्र संदेह व्यक्त कर रहे हैं। राव ने कहा कि आन्दोलन में बाहरी अवलोकन कर्ताओं की संख्या बढ़ी है। परन्तु हमें उनके आन्दोलन में रूचि लेने से हतोत्साहित नहीं होना है।30 उन्होंने विश्व में होने वाले परिवर्तनों की बात कहते हुए युगोस्लाविया का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि युगोस्लाविया गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के जन्मदाताओं में से एक है तथा यूरोप का एकमात्र प्रतिनिधि रहा है परन्तु दुर्भाग्यवश उसका विघटन हो चुका है। अब केवल साइप्रस ही इस महाद्वीप से गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अतः आज हमें और अधिक संगठित होने की आवश्यकता है।31

2. निष्कर्ष

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यह पहला अवसर था जब गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के 113 सदस्य 'सामूहिक आत्म-निर्भरता' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 'व्यावहारिक कदम' उठाने पर एकमत हो गए थे। भारत ने इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत ने

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र ओद्योगिक विकास संगठन को बनाए रखने और उन्हें मजबूत करने के लिए अपना पक्ष रखा और भारत के इन विचारों को स्वीकार किया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के पुनर्गठन तथा लोकतान्त्रिकरण को बढ़ावा देने तथा परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी आवाज उठाई। इसके अतिरिक्त भारत ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को द्विपक्षीय विवादों में घसीटने तथा दक्षिण एशिया को परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित करने के पाकिस्तान के प्रयास को विफल करके सम्मेलन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया।

संदर्भ ग्रन्थ

किसिंग रिकार्डस ऑफ़ वल्ड इवेन्ट्स, वॉ. 41, नं॰ 10, नवम्बर, 1995, पृ॰ 40803।

कांति बाजपेयी, ‘‘नैम एण्ड न्यू वल्ड आर्डर,’’ नेशनल हैरल्ड, नई दिल्ली, 25 अप्रेल 1996।

के॰वाई॰दाउद, नॉन-अलाईंड मूवमेंटः बेलग्रेड टू डरबन, कलिंगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1999, पृ॰ 43।

शैली मॉरफत, ‘‘द नॉन-अलाईड एण्ड दियर इलैवन्थ समिट्स एट कार्टेग्ना, अक्टूबर 1995’’, द राऊंड टेबल, वॉ. 340, नं॰ 13, अक्टूबर, 1995, पृ॰ 458।

वही।

‘‘दिस वल्ड इज ऑफर वल्ड टू-फिदेल,’’ थर्ड वल्ड रिसरजेन्स, नं॰ 64, दिसम्बर, 1995, पृ॰ 25।

भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा ग्यारहवें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में दिया गया भाषण, इलैवन्थ नैम समिट्सः सलैक्टिड डॉक्यूमेंटन्स, इंडियन इन्सटिटयूट फॉर नॉन -अलाईड स्ट्डिज, नई दिल्ली, 1996, पृ॰ 172।

‘‘निर्गुट सम्मेलन में भारत की कामयाबी,’’ नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1995।

‘‘निर्गुट देश प्राथमिकताएं बदलेगें’’, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1995।

यादिर फैरर, ‘नॉन -अलाईड मूवमेंट फॉर सूलिडेरिटी एण्ड को- ऑपरेशन’’, थर्ड वल्ड रिसरजेन्स, नं॰ 64, दिसम्बर 1995, पृ॰ 24।

डाक्यूमेन्ट्स, संख्या 7, पृ॰ 168।

के॰के॰ कत्याल, ‘‘रीगंल्स डीलेड़ नैम ड्राफ्ट’’ द हिन्दू, नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1995।

के॰के॰ कत्याल, ‘‘राव स्नब्स पाक फॉर रेजिंग कश्मीर इश्यू’’ द हिन्दू, नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1995।

वही।

नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 1995। 16. वही।

मनोरमा चतुर्वेदी, गुटनिरपेक्ष आन्दोलनः बदलता परिदृश्य, अंकुर प्रकाशन, उदयपुर 2006, पृ॰ 86।

इंडियन रिकॉडर, वॉ. 2ए नं॰ 47, 19-25 नवम्बर, 1995, पृ॰ 1570।

वही।

‘‘इलेवेन्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ़ हैड्स ऑफ़ स्टेट और गवर्नमैंट ऑफ़ नॉन - अलाईंड कन्ट्रीज, कार्टेग्ना 18-20 अक्टूबर, 1995’’ थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ़ नॉन अलाईंड मूवमैंटः डॉक्यूमेंटन्स 1961-1996, मिनिस्ट्री ऑफ़ एक्सटर्नल अफेयर्स, नई दिल्ली, (भारत) पृ॰ 1624।

वही, पृ॰ 1624-25।

‘‘पाक कश्मीर से पूरी तरह हटेः बेनजीर को राव की कड़ी फटकार,’’ नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1995। 23. एशियन रिकार्डर, वाॅ॰ ग्ग्ग्प् नं॰ 46, 12-18 नवम्बर, 1995, पृ॰ 25212।

वही, पृ॰ 25212।

कत्याल, संख्या 13।

‘‘नैम’स रियलिस्टिक व्यू ऑन वल्ड प्रॉब्लम्स’’ नेशनल हैरल्ड, नई दिल्ली, 25 अक्टूबर 1995।

एशियन रिकार्डर, संख्या 13, पृ॰ 25213।

हरि जयसिंह, ‘‘नैम स्टील रेलिवेन्टः राव’’, द ट्रिब्यून, चण्डीगढ़, 18 अक्टूबर 1995।

चिन्तामणी महापात्र, इंडिया मस्ट कन्सॉलिटेड इट्स नैम स्टेटस,’’ नैशनल हैरल्ड, नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1995। 30. इंडियन रिकार्डर, संख्या 18, पृ॰ 1571।

द पेट्रिऑट, कलकत्ता, 21 अक्टूबर, 1995।